WITWAVES
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
Vol-2 Issue-1
(International Peer-Reviewed E-Journal)
(January 2025)

शासकीय योजनाओं के क्षेत्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

भूमानी बाई अहिरवार
शोध छात्रा
महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

शोध सारांश
सरकार द्वारा समय-समय पर जनता के कल्याण के लिए नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया गया है आमजनता तक इन योजनाओं को पहुँचाने के लिए विभिन्न जनसंचार माध्यमों जैसे टेलीविजन, रेडियो, अखबार और वेबसाइट पर योजनाओं संबंधी जनता को सरकार द्वारा किए कार्यों के विषय में जानकारी मिलती रहती है। सरकारी सभी योजनाएँ समाज के विकास के लिए जरूरी है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में विभिन्न शासकीय योजनाओं के बारे में तथ्यात्मक जानकरी प्रस्तुत की गई है।

बीज शब्द
तथ्य, शासकीय, गुणवत्ता, प्रोत्साहित, क्षेत्र, उद्देश्य।

भूमिका

सरकारी योजनाएँ सरकार द्वारा सभी नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम हैं। सरकारी योजनाओं को आम तौर पर दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है- केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएँ। शासकीय योजनाएँ विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। प्रत्येक क्षेत्र की योजनाएँ विशिष्ट समस्याओं को हल करने, समाज के विभिन्न हिस्सों की भलाई सुनिश्चित करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की जाती हैं। निम्नलिखित में प्रमुख क्षेत्रों और उनके अंतर्गत आने वाली योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है -

स्वास्थ्य क्षेत्र - स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्न शासकीय योजनाएँ क्रियान्वयन में है -

- आयुष्मान भारत योजना: यह योजना भारत के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जिससे वे गंभीर बीमारियों का इलाज करवा सकते हैं।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM): यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, मातृ और बाल स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए बनाई गई है।
- स्वच्छ भारत मिशन: इसका उद्देश्य स्वच्छता और स्वास्थ्य के मानकों को बढ़ाना है, विशेष रूप से खुले में शौच से मुक्ति के लिए।

शिक्षा क्षेत्र - शिक्षा मनुष्य के जीवन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती पूर्ण व्यक्तित्व का विकास शिक्षा से ही सम्भव है। शिक्षा से संबंधित प्रमुख शासकीय योजनाएँ निम्नवत है
- सर्व शिक्षा अभियान (SSA): यह योजना हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए है, खासकर प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर।
- मिड-डे मील योजना: स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करने के लिए बनाई गई, जिससे उनकी स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार हो सके।
- राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना: यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र - व्यक्ति के जीवन की मूलभूत तीन आवश्यकताए होती है रोटी, कपड़ा और मकान व्यक्तियों के रहने की भी व्यवस्था सरकार करती है।आवास से संबंधित प्रमुख शासकीय योजनाए निम्न है -
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए सस्ते और पक्के आवास का निर्माण करना इस योजना का उद्देश्य है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: ग्रामीण इलाकों में सड़क नेटवर्क को सुधारने और विस्तारित करने के लिए बनाई गई है।
- स्मार्ट सिटी मिशन: शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए स्मार्ट तकनीकों का उपयोग करने के लिए।

कृषि और ग्रामीण विकास: भारत एक कृषि प्रधान देश है कृषि की उत्तम पैदावारी के लिए कृषक भाइयों की स्थिति सुद्रण करने के लिए विभिन्न शासकीय योजनाओं को क्रियान्वयन किया है -
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई गई है।

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS): ग्रामीण इलाकों में बेरोज़गारी को कम करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए रोजगार गारंटी प्रदान करती है।

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY): कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को समर्थन देती है।

सामाजिक सुरक्षा - समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिवार के पालन पोषण हेतु धन की आवश्यकता पड़ती है धन का अर्जन व्यक्ति शासकीय या निजी संस्थानों में नौकरी कर के करता है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए है उनकी आधारभूत आवश्यक ताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने कई लाभान्वित शासकीय योजनाओं को प्रराम्भ किया है -

- प्रधानमंत्री जन धन योजना: इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है, विशेष रूप से गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को।

- प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना: बुजुर्ग नागरिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना है।

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।

पर्यावरण और जल प्रबंधन - सरकार देश के पर्यावरण संतुलन के प्रति पूर्ण निष्ठावान है एवं देश में निरंतर पेय जल की कमी होती जा रही है इसके प्रति चिंतित भी है जल की कमी को पूर्ण करने एवं जल संरक्षण के लिए भी कई शासकीय योजनाओं को प्रारम्भ किया गया है।

- जल जीवन मिशन: इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

- नमामि गंगे योजना: गंगा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त करने के लिए यह योजना बनाई गई है।

- सोलर पैनल सब्सिडी स्कीम: नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

खेल और सांस्कृतिक विकास - खेल हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। खेल शरीर को स्वस्थ और मन को प्रफुल्लित बनाते है। खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने विभिन्न शासकीय योजनाओं को शुरू किया है -

- खेलो इंडिया: यह योजना युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, और आवश्यक संसाधनों के माध्यम से खेलों में प्रोत्साहित करती है।

- राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव: सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए योजनाएँ।

निष्कर्ष

देश में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं के अध्ययन उपरांत हमने यहीं जाना कि प्रत्येक क्षेत्र की योजनाएँ देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं और समाज के विभिन्न वर्गों की भलाई को सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं। ये योजनाएँ न केवल आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने का लक्ष्य रखती हैं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार और समग्र विकास को भी प्रोत्साहित करती हैं।

सन्दर्भ सूची

1. गुलाटी, अशोक एवं टिम केली (2003): व्यापार उदारीकरण और भारतीय कृषि, ऑक्सफोर्ड, नई दिल्ली।
2. जी. एस. भल्ला (2007): इंडियन एग्रीकल्चर सिंस इंडिपेंडेंस, एन.बी.टी. नई दिल्ली।
3. सिंह, करतार (2009): ग्रामीण विकास सिद्धांत, नीतियाँ और प्रबंधन, कृषि, तीसरा संस्करण।
4. विश्व बैंक (2008): विश्व विकास रिपोर्ट विकास के लिए कृषि, द वर्ड बैंक वाशिंगटन, डी.सी.।
5. मीणा, जनक सिंह (2010): ग्रामीण विकास के विविध आयाम.
6. त्रिपाठी, संजय (2010): छत्तीसगढ़ वृहद संदर्भ,
7. त्रिपाठी, राजपूत (2007) कृषक दूत. धान की उन्नत खेती, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर.
8. मिश्रा. जे.एस. पी.एस. वृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र, साहित्य भवन प्रकाशन।